उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आदेश सं. से अपील 2001 का 584

(पुराना नं. 1997 का 97)

उत्तर प्रदेश राज्य .....अपीलकर्ता

बनाम.

मेसर्स फूल चंद्रा .....प्रतिवादी

कोरमः माननीय सुधांशु धूलिया, जे.
माननीय आर.सी. खुल्बे, जे.

सुश्री बीना पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य की विद्वान स्थायी वकील/अपीलार्थी।
श्री नंदन आर्य, प्रतिवादी के अधिवक्ता।

माननीय सुधांशु धूलिया, जे. (मौखिक)

मध्यस्थता के मुख्य उद्देश्यों में से एक सख्त प्रक्रियात्मक कानूनों को समाप्त करके मामलों का त्वरित निपटान करना है। इसका उद्देश्य एक फास्ट ट्रैक प्रणाली होना था। फिर भी हमारे सामने एक मामला है, जिसका एक अनूठा और उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है, क्योंकि यह लगभग 25 वर्षों से अदालतों में है!

2. सिविल और इंजीनियरिंग कार्य के लिए ठेकेदार यानी मेसर्स फूल चंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य के सिंचाई विभाग के बीच दिनांक 22.03.1985 को एक समझौता निष्पादित किया गया था। बाद में पक्षों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ और मामले को मध्यस्थता खंड की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जो अनुबंध का एक हिस्सा था। मध्यस्थ ने 29.08.1994 को अपना पंचाट दिया। इसके बाद, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30/33 के तहत पंचाट को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे अदालत ने

दिनांक 10.05.1996 के फैसले और आदेश के तहत खारिज कर दिया था और पंचाट का नियम बना दिया गया था।

3. यूपी राज्य वर्ष 1997 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 39 के तहत एक अपील में दिनांक 10.05.1996 के आदेश को चुनौती दी गई, जहां यह लंबित रहा, और बाद में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद, (जिसे यूपी पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से अलग किया गया था), मामला क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

4. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 25.06.2007 के आदेश के तहत अपील को स्वीकार कर लिया और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के दिनांक 10.05.1996 के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से तय करने के निर्देश के साथ मामले को निचली अदालत में भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस न्यायालय की खंडपीठ की राय थी कि विद्वान सिविल जज ने उनके सामने मौजूद मुद्दों पर विचार किए बिना, मामले का फैसला "सरसरी तरीके" से किया था। दिनांक 25.06.2007 के इस आदेश को ठेकेदार (मैसर्स फूल चंद्र) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली। ऐसा करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आदेश को रद्द करना सही नहीं था कि यह "सरसरी" था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि विद्वान सिविल न्यायाधीश ने सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया था। यह निम्नानुसार देखा गयाः-

> “हमारा उपरोक्त दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है, कि अधिनियम की धारा 30 के तहत उठाई गई आपत्तियों पर विचार करते हुए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप से फैसला सुनाया था। वास्तव

में, पैराग्राफ 8 (यहां ऊपर दिए गए) में उच्च न्यायालय द्वारा उजागर किए गए सभी मुद्दों पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून द्वारा व्यक्तिगत रूप से विचार किया गया था। यह दूसरी बात है कि क्या उपरोक्त विचार वैध और कानूनी रूप से तय किया गया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता का मुद्दा हमारे समक्ष विचार का विषय नहीं है। हमारे विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मामले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून द्वारा पुनर्निर्णय के लिए भेजा जाना उचित था या नहीं।

चूंकि, हमारा विचार है कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून ने आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 8 और विशेष रूप से क्लॉज 1.45,1.46 और 1.47 में उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई सभी आपत्तियों पर विचार किया था, उच्च न्यायालय मामले को दोबारा फैसले के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून के पास भेजना उचित नहीं था। "

5. इस प्रकार, मामले को नए फैसले के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष फिर से आया, तो इस बार इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 14.03.2014 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया। प्रवर्तनशील भाग इस प्रकार हैं:

"4. हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को हमारे सामने भेज दिया। तदनुसार, अपील पर पुनः सुनवाई की जाती है। हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और प्रतिवादी की ओर से पेश वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।

5. अपीलकर्ता का तर्क है कि मध्यस्थ को कारण बताना आवश्यक था; उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, और मध्यस्थ ने ऊपर दिए गए अनुबंध

के खंड 1.45, 1.46 और 1.47 के प्रभाव पर विचार नहीं किया। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की ओर से उक्त विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर समाप्त होता है।

6. मामला केवल अपीलकर्ता को यह उजागर करने की अनुमति देने के उद्देश्य से हमारे पास वापस भेजा गया था कि, जिन मुद्दों पर विचार किया गया था, उन पर विचार करते समय, मध्यस्थ ने स्वयं कदाचार किया। इस तरह का कोई तर्क नहीं दिया गया है। तदनुसार, हम अपील को खारिज करते हुए इसे समाप्त करते हैं।"

6. इस बार उत्तर प्रदेश राज्य इस मामले को शीर्ष अदालत में ले गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2015 के तहत फिर से अपील की अनुमति दी और मामले को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ फिर से इस न्यायालय को भेज दिया गया:-

"उच्च न्यायालय द्वारा 25.06.2007 को पारित पहले के विवादित आदेश को ऊपर दी गई टिप्पणी के साथ इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून ने पहले ही उन मुद्दों पर फैसला सुनाया था जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, और इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए मामले को पुनः निर्णय के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून को भेजना उचित नहीं था।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2014 के अपने आदेश में दर्ज की गई स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जा रहा है, जिससे प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा गुण-दोष के आधार पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करने और कानून के अनुसार उस पर

निर्णय देने की आवश्यकता होगी। ऐसा करते समय, हम दिनांक 14.03.2014 के विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं। पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से 03.11.2015 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अपील उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है"

7. इन परिस्थितियों में, मामला निर्णय के लिए इस न्यायालय के समक्ष आया है।

8. हमने पार्टियों को विस्तार से सुना है।

9. यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत एक अपील है, उस आदेश के खिलाफ जिसके द्वारा न्यायालय ने मध्यस्थता पंचाट को रद्द करने से इनकार कर दिया है, और पंचाट को न्यायालय का नियम बना दिया है।

10. किसी पंचाट को रद्द करने का आधार पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 में दिया गया है, जो इस प्रकार है:

"30. पंचाट को रद्द करने का आधार । निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों को छोड़कर किसी भी पंचाट को रद्द नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

(ए) कि किसी मध्यस्थ या अंपायर ने स्वयं या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया है।

(बी) कि मध्यस्थता को अधिक्रमण करने वाले न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने के बाद या धारा 35 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही अमान्य हो जाने के बाद कोई पंचाट दिया गया है;

(सी) कि कोई पंचाट अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है या अन्यथा अमान्य है।

11. हमने दिनांक 29.08.1994 के पंचाट को देखा है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी को देहरादून के पास एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करना था जिसे "खारा पावर प्रोजेक्ट" के नाम से जाना जाता है। 22.03.1985 को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और ठेकेदार के बीच एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। यह मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए टर्बाइनों तक पानी ले जाने के लिए एक चैनल का निर्माण था। परियोजना के पूरा होने के बाद, ठेकेदार द्वारा विभिन्न मदों में धन की मांग की गई, जैसे किः उपकरण की क्षति के कारण ठेकेदार को हुआ नुकसान; विभाग की ओर से देरी; कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, आदि।

12. इस संबंध में, अनुबंध के तीन महत्वपूर्ण खंड हैं, जिनका अब हम उल्लेख करेंगे। ये खंड 1.45, 1.46 और 1.47 हैं, जो निम्नानुसार हैं:

> "1.45: यदि ठेकेदार इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान के संबंध में प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधियों के किसी भी रिकॉर्ड या फैसले को अनुचित मानता है या प्रभारी अभियंता द्वारा उससे मांगे गए किसी भी कार्य को अनुबंध से बाहर मानता है। अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार, ऐसे काम की मांग होने पर वह तुरंत लिखित निर्देशों या निर्णयों के लिए लिखित में मांगेगा, जिसके प्राप्त होने पर वह फैसले के रिकॉर्ड की पुष्टि करने या मांगे गए कार्य को करने के लिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ेगा और 15 दिनों के भीतर लिखित निर्देशों या निर्णयों की प्राप्ति की तारीख के बाद वह अपनी आपत्ति का आधार स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताते हुए प्रभारी अभियंता को लिखित विरोध दर्ज करा सकता है। ऐसे विरोधों या आपत्तियों को छोड़कर जो यहां निर्दिष्ट तरीके से और बताई गई समय सीमा के भीतर रिकॉर्ड पर किए गए हैं, प्रभारी अभियंता के फैसले, निर्देश या निर्णय निर्णायक और ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे। ठेकेदार को चित्र भेजने वाले पत्रों में शामिल प्रभारी अभियंता के निर्देशों और/या निर्णयों को लिखित निर्देश या निर्णय माना जाएगा, जो यहां दिए गए विरोध या आपत्तियों के अधीन होगा ।

1.46: यदि ठेकेदार खंड 1.45 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठेकेदार द्वारा किए गए विरोध या आपत्ति पर प्रभारी अभियंता के अंतिम निर्णय से असंतुष्ट है, तो ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के बाद अट्ठाईस (28) दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को लिखित में नोटिस दें कि मामले को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए और विवाद या अंतर 2 का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें मुद्दे पर लाभ को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए। यदि ठेकेदार ऊपर निर्धारित 28 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा नोटिस देने में विफल रहता है तो प्रभारी अभियंता का निर्णय निर्णायक और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

1.47: प्रत्येक विवाद मतभेद या प्रश्न जो किसी भी समय पार्टियों के बीच या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति के बीच उत्पन्न हो सकता है, इस विलेख या उसके विषय के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकता है, मुख्य अभियंता या उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया मध्यस्थ एक सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों से निपटना है जिनसे अनुबंध संबंधित है और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उन्होंने विवाद या मतभेद वाले सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे। जिस मध्यस्थ के पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, उसका स्थानांतरण होने या उसका कार्यालय खाली होने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में मुख्य अभियंता या तो स्वयं संदर्भ में प्रवेश करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उस स्थिति से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिसे पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। इस अनुबंध की एक शर्त यह भी होगी कि उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है तो

मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा। सभी मामलों में जहां विवाद में दावे की राशि रु. 50,000 (पचास हजार रुपये) और इससे अधिक की राशि के लिए मध्यस्थ को पंचाट के लिए कारण बताना होगा। "

13. माना जाता है कि ठेकेदार के अनुरोध के अनुसार, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने अपने आदेश दिनांक 19.02.1992 द्वारा श्री सुरेश चंद्र गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। दावे के दावे और आपत्तियाँ विद्वान मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत की गईं। ये दावे 'ए' से 'क्यू' तक 17 शीर्षकों के अंतर्गत थे। ठेकेदार के दावों और विभाग की आपत्तियों को सुनने के बाद, प्रत्येक दावे पर मध्यस्थ द्वारा अलग से निर्णय लिया गया और कुल दावा रु. 25,72,944/ (पच्चीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ चौवालीस रुपये मात्र) के मुकाबले 5,08,232/- रुपये (पांच लाख आठ हजार दो सौ बत्तीस रुपये मात्र) की राशि प्रदान की गई। ।

14. ब्याज के लिए, मध्यस्थ ने पंचाट की तारीख तक 18% की दर से साधारण ब्याज इस प्रकार दिया है:

"30.04.91 से 29.08.1994 तक (पंचाट की तिथि) सभी दावों पर ("एन" को छोड़कर) रु. 3,51,131.00 की राशि

दावा "एन" (प्रतिभूति और बकाया राशि का धनवापसी) पर 30.10.1991 से 29.08.1994 तक रु 2,50,000.00 राशि.

इसके अलावा रुपये 5,08, 232.00 पर 6% (छह प्रतिशत) प्रति वर्ष का ब्याज पंचाट की तिथि से भुगतान या डिक्री तक, जो भी पहले हो। "

15. दो बुनियादी आपत्तियां हैं जो अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत के साथ-साथ हमारे समक्ष भी उठाई गई हैं। पहला यह है कि ठेकेदार (हमारे सामने प्रतिवादी) के दावे समय-बाधित थे, और इसलिए मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी

नहीं थे, और ऐसा करके उन्होंने खुद को गलत तरीके से संचालित किया है। दूसरे, अपना पंचाट देते समय मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।

16. खंड 1.45 और 1.46 को पढ़ने से पता चलता है, जिन्हें ऊपर संदर्भित किया गया है, कि यदि ठेकेदार द्वारा कोई मांग उठाई जानी है तो उसे इंजीनियर से निर्देश या निर्णय के लिए लिखित रूप में पूछना होगा और उसके बाद 15 दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर वह प्रभारी अभियंता के समक्ष "अपनी आपत्तियों का आधार स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताते हुए" विरोध दर्ज करेगा। प्रभारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा, लेकिन यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है कि मामले को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए। यह संक्षेप में अनुबंध के दो खंड यानी खंड 1.45 और 1.46 कहते हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

17. तथ्य यह है कि हमारे पास इस संबंध में प्रभारी अभियंता का कोई लिखित आदेश नहीं है और न ही ठेकेदार का कोई विरोध है। हालाँकि, हमारे पास सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का दिनांक 19.02.1992 का आदेश है, जिसके तहत उन्होंने श्री सुरेश चंद्र गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था। उपरोक्त आदेश के मद्देनजर विरोध दर्ज कराने और इस तरह उस पर निर्णय देने की औपचारिकताओं का फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि स्वयं मुख्य अभियंता ने ही इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया था।इसलिए, एक धारणा बनाई जाएगी कि मुख्य अभियंता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह एक मध्यस्थता विवाद है, क्योंकि तभी उन्होंने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा होगा।

18. इसके अलावा, यह दलील कि दावे समयबाधित हैं, गलत है, क्योंकि 28 दिन की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब ठेकेदार का दावा इंजीनियर प्रभारी द्वारा

खारिज कर दिया गया था। माना कि ऐसा कोई औपचारिक आदेश नहीं है जिसके द्वारा ठेकेदार का दावा खारिज किया गया हो। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ठेकेदार द्वारा 28 दिनों के भीतर आपत्तियां नहीं की गईं। इसके अलावा, मुख्य अभियंता प्रभारी का एक आदेश है जिसमें स्वयं स्वीकार किया गया है कि 20.11.1991 और 21.12.1991 को कुछ प्रमुखों पर आपत्तियां की गई थीं, और इसलिए, अब मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। मध्यस्थ की नियुक्ति न्यायालय के किसी आदेश से नहीं की गई थी, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ठेकेदार द्वारा दिनांक 20.11.1991 को दिए गए एक आवेदन पर मध्यस्थ की नियुक्ति स्वयं प्रभारी अभियंता द्वारा की गई थी। इसलिए, यह माना जाएगा कि ठेकेदार के दावे और मध्यस्थ की नियुक्ति सीमा के भीतर थी और समय बाधित नहीं थी, अन्यथा सबसे पहले अपीलकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की होती।

19. आदेश दिनांक 19.02.1992 अनुबंध और फिर ठेकेदार के पत्र दिनांक 20.11.1991 को संदर्भित करता है, जहां उन्होंने 'ए' से 'क्यू' तक कुछ आपत्तियां उठाई हैं यानी 17 आपत्तियां जिन्हें उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.12.1991 में दोहराया है कि एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा रहा है जो श्री सुरेश चंद्र गुप्ता हैं। यूपी राज्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों की संख्या दिनांक 10.05.1996 के आदेश में भी बताई गई है, जिसमें 'ए' से 'क्यू' तक अलग-अलग शीर्ष हैं, जिस पर ठेकेदार द्वारा कुछ धनराशि की मांग की गई थी।

20. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार खंड 1.47 के संबंध में है जो कहता है कि:

> "उन सभी मामलों में जहां विवाद में दावे की राशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक है, मध्यस्थ को पंचाट के लिए कारण बताना होगा।"

21. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क था कि चूंकि दावा 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) से अधिक का था, इसलिए पंचाट में मध्यस्थ द्वारा कारण बताए

जाने चाहिए थे। कानून, जैसा कि पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत था, यह था कि मध्यस्थ के लिए अपना पंचाट देते समय कारण बताना आवश्यक नहीं था। हालाँकि, हमें लगता है कि एक बार अनुबंध में एक निर्धारित शर्त थी, जिसमें कहा गया था कि 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) से अधिक के दावे के लिए कारण बताए जाएंगे, तो कारण दिए जाने चाहिए थे।

22. अब आइए उन कारणों को देखें जो मध्यस्थ ने अपना पंचाट देते समय बताए हैं। हमने दिनांक 29.08.1994 के पंचाट का अवलोकन किया है। विद्वान मध्यस्थ ने ठेकेदार द्वारा उठाए गए प्रत्येक दावे और उसमें मौजूद आपत्तियों पर अपना दिमाग लगाया है। मध्यस्थ के पंचाट 29.08.1994 में ठेकेदार (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी मेसर्स फूल चंद्र) के प्रत्येक दावे (कुल 17) के गुण और दोषों पर चर्चा की गई है और इसके बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कितना पंचाट दिया जाना चाहिए, यदि दिया जाए तो। ये विस्तृत कारण नहीं हैं और यह फिर से आवश्यकता भी नहीं है। यहां देखने वाली बात यह है कि क्या उठाए गए दावों पर मध्यस्थ द्वारा दिमाग का इस्तेमाल किया गया था। हमने पाया कि यह मानदंड पूरा कर लिया गया है। यह जानने के लिए कि प्रत्येक शीर्षक के तहत पंचाट कैसे दिया गया, हम यहां दावे 'ए' का उल्लेख कर सकते हैं जो कि "बुलडोजर के परिवहन के कारण कई स्थानों पर संदर्भ सह जल निकासी के उल्लंघन के कारण हमें हुए नुकसान के दावे के रूप में देय भुगतान" के लिए था और उसके परिणामस्वरूप हानि। " इस पर मध्यस्थ का निर्णय इस प्रकार थाः

> "दावेदारों ने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकताओं के अनुसार संदर्भ सह-जल निकासी का निर्माण किया था। दावेदारों ने शुरू में प्रतिवादियों को विभागीय बुलडोजर से इसकी क्षति के बारे में सूचित किया और अपने पत्र दिनांक 21.10.86 के माध्यम से निरीक्षण का अनुरोध किया।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विभागीय मशीनों द्वारा संदर्भ-सह-जल निकासी को कोई क्षति नहीं हुई है और दावेदार इस संबंध में प्रभारी अभियंता के मौखिक निर्णय से संतुष्ट थे।

मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, विभागीय उपकरणों की आवाजाही के कारण संदर्भ-सह-जल निकासी की क्षति हुई है। यद्यपि दावा किया गया नुकसान अत्यधिक है। प्रतिवादियों के अनुसार मुआवजे का अनुमान रु. 58.00 प्रति मीटर उचित माना जाता है। यह केवल 3,480.00 रुपये बनता है जो दावेदारों के पक्ष में दिया जाता है। "

23. इसी प्रकार, दावा 'बी' जो वन विभाग द्वारा खदान के गैर-आवंटन और परिणामस्वरूप बैरी और रेत जैसी निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण दावे के रूप में देय भुगतान के लिए था। मध्यस्थ का निर्णय इस प्रकार थाः

"यह दावा वन विभाग द्वारा खदान की अनुपलब्धता के संबंध में है। जिसके कारण दावेदार निर्माण सामग्री प्राप्त नहीं कर सके और इसलिए काम की शुरुआत में 20 महीने और एक सप्ताह तक उनका श्रम और मशीनरी बेकार पड़ी रही। काम पूरा होने में अत्यधिक देरी के कारण, दावेदार ने भी दावा (दावा एल) को प्राथमिकता दी है। चूंकि यह दावा (दावा बी) भी प्रारंभिक देरी के कारण है, इसलिए इसे दावे-एल के साथ जोड़ा जा रहा है और इसके साथ विचार किया जा रहा है।

24. एक मध्यस्थ द्वारा जो कारण बताए जाने हैं, उन्हें विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को बस यह देखना है कि क्या मध्यस्थता विवाद के प्रति सक्रिय थी और उसने अपने फैसले पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है । मध्यस्थ के आदेश को पढ़ने के बाद, हमारे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक शीर्ष के तहत मध्यस्थ द्वारा कारण बताए गए हैं।

25. पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत यह जांचना भी इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि क्या मध्यस्थ एक अलग दृष्टिकोण

अपना सकता है। इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मध्यस्थ ने विवाद पर फैसला सुनाते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। हमें यह नहीं दिखाया गया है कि मध्यस्थ द्वारा बताए गए कारण गलत हैं या मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमारे लिए पंचाट में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा (भारतीय खाद्य निगम वी. जोगिंदरपाल मोहिंदरपाल और अन्य, एआईआर 1989 एससी 1263)। भारतीय खाद्य निगम (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना था:

> "8. मौजूदा मामले में, मध्यस्थ ने तर्कसंगत पंचाट देना चुना है, यानी उसने अपने निष्कर्ष के लिए कारण बताए हैं। वह ऐसे कारण बताने के लिए बाध्य है या नहीं, यह एक और मामला है, लेकिन चूंकि मध्यस्थ ने कारण बताने का फैसला किया है, जब तक कि इस न्यायालय को यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि ऐसे कारण गलत हैं जैसे कि कानून के प्रस्ताव या एक दृष्टिकोण जो मध्यस्थ ने लिया है, वह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे संभवतः मामले के किसी भी दृष्टिकोण पर कायम नहीं रखा जा सकता है, तो मध्यस्थ के पंचाट को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसा कि सुदर्शन ट्रेडिंग बनाम केरल सरकार, (1989) 1 जेटी 339 में जोर दिया गया है:(एआईआर 1989 एससी 890) कि यदि मध्यस्थ ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया है या अधिकार क्षेत्र से परे आगे बढ़ा है तो एक पंचाट को रद्द किया जा सकता है। जहां पंचाट में स्पष्ट त्रुटियां हों, वहां इसे रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन ये अलग और विशिष्ट आधार हैं। पंचाट के प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटियों के मामले में, इसे केवल तभी रद्द किया जा सकता है यदि पंचाट में कानून का कोई प्रस्ताव हो जो पुरस्कार के प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो अर्थात्, स्वयं पंचाट में ही या पंचाट में शामिल किसी दस्तावेज़ में। चैम्पसी भारा एंड कंपनी बनाम जीवराज बालू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड में

न्यायिक समिति की टिप्पणियाँ देखें, (1923) 50 इंडस्ट्रीज़ ऐप 324: (एआईआर 1923 पीसी 66)"

26. उसी मामले में यानी भारतीय खाद्य निगम (ऊपर) में, यह निम्नानुसार कहा गया था:

"हालांकि, मध्यस्थता की कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और ऐसी प्रथा और प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए जिससे विवाद का उचित समाधान हो सके और उन लोगों का विश्वास पैदा हो जिनके लाभ के लिए इन प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। इसलिए, यह निगरानी करना कानून की अदालतों का कार्य है कि मध्यस्थ न्याय के मानदंडों के भीतर कार्य करें। एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं और पंचाट स्पष्ट, उचित और निष्पक्ष हो जाता है, तो अदालतों को, जहां तक संभव हो, पक्षों के पंचाट को प्रभावी बनाना चाहिए और पक्षों को अपने चुने हुए निर्णायक के निर्णय का पालन करने और उसका पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में किसी को मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट में न्यायालय द्वारा सुधार की गुंजाइश और सीमा को देखना चाहिए। हमें मध्यस्थता के कानून को सरल, कम तकनीकी और स्थितियों की वास्तविक वास्तविकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना चाहिए लेकिन न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और मध्यस्थ को ऐसी प्रक्रिया और मानदंड का पालन करने के लिए बाध्य करें जो न केवल पक्षों के बीच न्याय करके विश्वास पैदा करेंगे, लेकिन यह समझ पैदा करने से कि न्याय हो गया प्रतीत होता है। "

27. हालाँकि, तीसरा पहलू भी है, जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज के संबंध में है। विद्वान मध्यस्थ ने 30.04.1991 से 29.08.1994 (अर्थात् पंचाट की तिथि) तक सभी दावों ("एन" को

छोड़कर) पर 18% का वाद लंबित रहने तक का ब्याज रु. 3,51,131.00/- की राशि का और रु. 5,08, 232.00/- पर 6% प्रति वर्ष का ब्याज, पंचाट की तिथि से भुगतान या डिक्री तक, जो भी पहले हो, दिया है।

28. हमारी राय है कि विद्वान मध्यस्थ को वाद लंबित रहने तक का ब्याज नहीं देना चाहिए था। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की खंड 29 निम्नानुसार हैः

> "29. **पंचाट पर ब्याज**। जहां और जहां तक कोई पंचाट पैसे के भुगतान के लिए है, तो न्यायालय डिक्री में, डिक्री की तारीख से ऐसी दर पर ब्याज का आदेश दे सकता है, जिसे न्यायालय उचित समझे, मूल राशि पर भुगतान किया जाना है जैसा कि पंचाट द्वारा निर्धारित किया गया है और डिक्री द्वारा पुष्टि की गई। "

29. मध्यस्थता कार्यवाही में तीन चरण होते हैं। पहला चरण विवाद की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि है जब मामला अंततः मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। दूसरा चरण मध्यस्थ द्वारा अपना पंचाट देने में ली गई अवधि है और तीसरा चरण वह चरण है जिसके दौरान पंचाट न्यायालय का नियम बन जाता है। उपरोक्त प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि केवल न्यायालय ही ब्याज दे सकता है और दूसरी बात यह कि ब्याज केवल डिक्री की तारीख से ही दिया जाना चाहिए यानी तीसरे चरण के समापन पर "ऐसी दर पर जो अदालत उचित समझे"।

30. ***एआईआर 1988 एससी 1520*** में रिपोर्ट किए गए ***कार्यकारी अभियंता, सिंचाई, गलीमाला और अन्य बनाम अबनादुता जैना*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम और ब्याज अधिनियम के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में उपरोक्त प्रावधान पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है और न ही पंचाट की कार्यवाही लंबित होने तक। ब्याज मात्र अदालत द्वारा ही दिया जा सकता है। इसमें कहा गया हैः

"जिन मामलों में 1978 का ब्याज अधिनियम कार्यवाही से पहले ब्याज का पंचाट लागू होता है, उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। वाद लंबित रहने तक के ब्याज के संबंध में, यानी संदर्भ की तारीख से पंचाट की तारीख तक का ब्याज, साधारण कारण से दावेदार इसके हकदार नहीं होंगे कि मध्यस्थ सी.पी.सी. की धारा 34 के अर्थ के अंतर्गत एक न्यायालय नहीं है, न ही मुकदमों के दौरान मध्यस्थता का संदर्भ दिया गया था। ब्याज अधिनियम, 1978 के प्रारंभ होने से पहले उत्पन्न हुए मामलों में, दावेदार कार्यवाही शुरू होने से पहले या मध्यस्थता के लंबित रहने के दौरान ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं। वे मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि के लिए ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि ब्याज अधिनियम, 1939 उनके मामलों पर लागू नहीं होता है और ब्याज का भुगतान करने के लिए कोई समझौता नहीं है या व्यापार का कोई भी उपयोग जिसमें कानून का बल हो या कानून का कोई अन्य प्रावधान जिसके तहत दावेदार ब्याज वसूलने के हकदार थे। वे वाद लंबित रहने तक का ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि मध्यस्थ कोई न्यायालय नहीं है और न ही मुकदमों में मध्यस्थता के संदर्भ दिए गए थे। "

31. इस निर्णय का बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***एआईआर 1990 एससी 1426*** में रिपोर्ट किए गए ***रायपुर विकास प्राधिकरण बनाम चौखामल ठेकेदार*** मामले में पालन किया गया ।बहरहाल, सिंचाई विभाग के मामले में यह मामला माननीय शीर्ष न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आया ***उड़ीसा राज्य बनाम जी.सी. रॉय, (1992) 1 एससीसी 508*** में रिपोर्ट किया गया, जहां यह माना गया कि कुछ आकस्मिकताओं पर कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ द्वारा ब्याज भी दिया जा सकता है। इसे निम्नानुसार वर्णित किया गया थाः

"43. यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्यस्थ के पास कार्यवाही के दौरान का ब्याज देने की शक्ति है, और यदि हां, तो किस सिद्धांत पर। हमें यह दोहराना चाहिए कि हम उस स्थिति से निपट रहे हैं जहां समझौता इस तरह के ब्याज के अनुदान का प्रावधान नहीं करता है और न ही इस तरह के अनुदान पर रोक लगाता है। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां समझौते में ब्याज देने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं:

(i) धन के उपयोग से वंचित व्यक्ति जिसे वह वैध रूप से हकदार है, उसे अभाव के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से कहें। इसे ब्याज, क्षतिपूर्ति या नुकसान कहा जा सकता है। यह मूल विचार उस अवधि के लिए उतना ही मान्य है जब विवाद मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, जितना कि मध्यस्थ द्वारा संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 का सिद्धांत है और मध्यस्थ के मामले में अन्यथा मानने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है।

(ii) पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ एक वैकल्पिक रूप (एसआईसी फोरम) है। यदि ऐसा है, तो उसके पास पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मध्यस्थ के पास वाद लंबित रहने की अवधि पर ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है, तो दावा करने वाले पक्ष को उस उद्देश्य के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, भले ही उसने मध्यस्थ से अन्य दावों के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली हो। इससे कार्यवाही की बहुलता हो जाएगी।

(iii) एक मध्यस्थ एक समझौते का निर्माता होता है। यह पक्षकारों के लिए खुला है कि वे उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान करें और उसके पालन के लिए

ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें, जैसा कि वे उचित समझें, जब तक कि वे कानून का विरोध न करें। (मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 और धारा 3 का प्रावधान इस बिंदु को स्पष्ट करता है)। फिर भी, समझौता कानून के अनुरूप होना चाहिए। मध्यस्थ को भी देश के सामान्य कानून और समझौते के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपना पंचाट देना चाहिए।

(iv) वर्षों से, अंग्रेजी और भारतीय न्यायालयों ने इस धारणा पर काम किया है कि जहां समझौता निषेध नहीं करता है और संदर्भ का एक पक्ष ब्याज के लिए दावा करता है, मध्यस्थ के पास वाद लंबित रहने तक का ब्याज देने की शक्ति होनी चाहिए। थावरदास फेरुमल बनाम भारत संघ का इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में पालन नहीं किया गया है। इसे इस आधार पर समझाया और अलग किया गया है कि उस मामले में ब्याज के लिए कोई दावा नहीं था, बल्कि केवल अनिश्चित क्षति के लिए दावा था। यह बार-बार कहा गया है कि उक्त निर्णय की टिप्पणियों का उद्देश्य ऐसा कोई पूर्ण या सार्वभौमिक नियम निर्धारित करना नहीं था जैसा कि वे पहली नज़र में प्रतीत होते हैं। सिंचाई विभाग बनाम अभदुता जेना तक देश की लगभग सभी अदालतों ने वाद के लंबित रहने तक का ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति को बरकरार रखा था। निरंतरता और निश्चितता कानून की अत्यंत वांछनीय विशेषता है।

(v) वाद लंबित रहने तक का ब्याज वास्तविक कानून का मामला नहीं है, जैसे संदर्भ से पहले की अवधि के लिए ब्याज (पूर्व-संदर्भ अवधि)। पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सदैव ऐसी शक्ति का अनुमान लगाया गया है।

44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि निम्नलिखित सही सिद्धांत है जिसका इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:-

जहां पार्टियों के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां एक पार्टी ब्याज का दावा करती है और वह विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को भेजा जाता है, उसके पास वाद लंबित रहे तक का ब्याज देने की शक्ति होगी। ऐसा इस कारण से है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पक्षों के बीच समझौते की एक निहित शर्त थी और इसलिए जब पक्ष अपने सभी विवादों को संदर्भित करती हैं या ब्याज के रूप में विवाद को मध्यस्थ के पास भेजती हैं, तो उसके पास ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में मध्यस्थ को आवश्यक रूप से वाद लंबित रहने तक का ब्याज का भुगतान करना चाहिए। यह उसके विवेक का मामला है कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाए।

32. बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अंबिका कंस्ट्रक्शन के मामले में इसका पालन किया गया, (2016) 6 एससीसी 36*** में रिपोर्ट किया गया।

33. दूसरे शब्दों में, एक मध्यस्थ वाद लंबित रहने की स्थिति में भी ब्याज दे सकता है, यहां तक कि जहां समझौते में ब्याज का प्रावधान नहीं है, या ब्याज देने पर रोक नहीं है।

34. हालाँकि, वर्तमान मामले में, अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 1.9 में एक विशिष्ट प्रावधान है। अनुबंध की विशेष शर्तों का खंड 1.9 इस प्रकार है:-

"**1.9:विवाद आदि के कारण भुगतान में देरी के लिए कोई दावा नहीं।** आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता के बीच किसी भी विवाद, अंतर या उसकी समझ के कारण सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज या हर्जाने के किसी भी दावे पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

35. दूसरे शब्दों में, एक विशिष्ट शर्त है जो ब्याज के किसी भी दावे को रोकती है।

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी मत है कि जहां तक ब्याज के पंचाट का संबंध है, उसे संशोधित करने की आवश्यकता है। विद्वान मध्यस्थ ने पंचाट की तारीख तक 18% की दर से ब्याज दिया है, जो हमारा मानना है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र या शक्तियों में नहीं था, विशेष रूप से समझौते में विशिष्ट खंडों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है। इसलिए, उस अवधि तक प्रतिवादी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। विद्वान मध्यस्थ ने आगे पंचाट की तारीख से भुगतान होने तक 6% की दर से ब्याज भी दिया है। हम उस हिस्से को भी संशोधित करते हैं, क्योंकि ब्याज मात्र डिक्री की तिथि से दिया जा सकता है। पंचाट और आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अब प्रतिवादी को डिक्री की तारीख यानी 10.05.1996 से उसके भुगतान तक केवल 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा।

37. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों और तर्क के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि पर 6% की दर से ब्याज का हकदार होगा, यानी 5,08,232/- (पांच लाख आठ हजार दो सौ बत्तीस रुपये केवल), डिक्री की तारीख से यानी 10.05.1996 से।

(रमेश चंद्र खुल्बे, जे.) (सुधांशु धूलिया, जे.)

11.03.2019

बलवंत/सुखबंत